ICAR Coordination Committee Meeting for Uttar Pradesh on Doubling Farmers' Income by March-2022

20th March 2017, Izatnagar

The Hon'ble Prime Minister while addressing a farmers' rally in Bareilly, Uttar Pradesh, on 28th February, 2016 shared his vision on doubling the farmers' income by the time the nation celebrates her 75 years of independence in the year 2022. Towards realizing this vision of Hon'ble Prime Minister, the ICAR has set-up Coordination Committee for all the states to chalk out strategies to double the farmers' income by March-2022.

A two-day meeting of Coordination Committee for Uttar Pradesh started at ICAR-Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar today.

Dr Arvind Kumar, Vice- Chancellor, Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi and Chairman of the Committee elaborated in great details the problems and priorities in the state. He said the yield for many crops and livestock species is much lower in UP than the national average in many cases. There lies a big opportunity to make improvement in yield enhancing through suitable interventions. The state being one among the biggest states with lot of diversity has very high potential which needs to be harnessed by working in desired directions. The commercialization in farming activities is missing in many parts of the state. He expressed the hope that this Committee would be able to work out a practical strategy capable of doubling the farmers' Income by March 2022 as desired by Hon'ble Prime Minister of India.

Dr R K Singh, Director, ICAR-IVRI and Convener of the meeting presented the background document and agenda of the meeting stating that the strategy to double the income of farmers need inputs and dedicated commitment from all sectors including animal husbandry, fisheries, poultry, horticulture, cereal crops, medicinal plants etc. In his presentation, he urged the agri-institutions in the state to come out with clear-cut actionable points so that an implementable strategy could be chalked out in coming days towards doubling the income of farmers.

Over 42 directors of ICAR institutes, their representatives, officials of line departments, scientists and officers of central agencies like Central Water Commission, Ministry of Food Processing Industries etc are attending this meeting.

Press and Media:

किसान की आय दोगुनी का खींचा खाका

प्रदेश भर के कृषि विशेषज्ञ एवं अफसरों ने आइवीआरआइ में दो दिन किया मंथन

जागरण संवाददाता, बरेली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली से बड़ा एलान कर चुके हैं। वह कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। उनका यह वादा सिर्फ वादा न रह जाए, इसलिए शिद्दत से धरातल पर उतारने की मुहिम शुरू कर दी गई है। वो भी बरेली से ही। इसके लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) में दो दिन से एक्सपर्ट की फौज जुटी है। बुधवार को उनकी अंतिम बैठक थी, जिसमें किसान की आय दोगुनी करने का लगभग खाका खींच दिया गया। अब यह प्रस्ताव 15 अप्रैल तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) में जमा होगा।

हां, इससे पहले कमेटी के चेयरमैन एवं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डॉ.अरविंद सिंह और कन्वेनर एवं आइवीआरआइ के निदेशक डॉ.आरके सिंह ने किसानों की राय लेने का भी फैसला किया है। इसके अलावा उप्र के उन्नतशील किसानों से भी जल्द राय ली जाएगी। बैठक में कृषि मंत्रालय के निर्देश पर आइसीएआर की ओर से गठित 27 सदस्यीय अपेक्स कमेटी के सदस्य शामिल हुए। उप्र की अपेक्ट कमेटी की पहली बैठक सोमवार से आइवीआरआइ में शुरू हुई थी, जो मंगलवार शाम तक चली। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ और अफसरों ने फसल लागत कम करने के साथ ही आय बढ़ाने पर मंथन किया। एक-एक विशेषज्ञ और अफसर का सुझाव शामिल कर प्रस्ताव तैयार किया गया। सभी प्रदेशों की अपेक्स कमेटी अपने प्रस्ताव 15 अप्रैल तक जमा करेंगी। इसके बाद कृषि मंत्रालय में चर्चा होगी। वहां प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर अलग-अलग राज्यों के हिसाब से प्रस्ताव लागू होगा ताकि किसानों की आय 31 मार्च-2022 तक दोगुनी हो सके।

मोदी का मिशन

- कृषि मंत्रालय में 15 अप्रैल तक जमा किया जाएगा उप्र का प्रस्ताव
- किसानों से राय लेने की बनी सहमति, दो दिवसीय बैठक संपन्न

मोदी ने कहा था

28 फरवरी-2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बरेली के फतेहगंज पश्चिमी स्थित रबर फैक्ट्री मैदान पर किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की घोषणा की थी। पीएम की घोषणा के बाद कृषि मंत्रालय ने आइसीएआर को हर राज्य से किसानों की आय दोगुनी करने का प्रस्ताव मांगा है।

कमेटी के यह प्रस्ताव

आय दोगुनी करने के प्रस्ताव में आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही समय से मिट्टी की जांच, कृषि योजनाओं में बदलाव, उन्हें सही तरीके से लागू करने, नई योजनाओं को बनाने, पशुओं को बढ़ावा देने की योजना लागू करना आदि शामिल हैं।

उप्र में कृषि सुधार की अधिक हैं संभावनाएं

जागरण संवाददाता, बरेली : उप्र में सभी कृषि संसाधन मौजूद हैं लेकिन किसान फायदा नहीं लेते। किसान संसाधनों का प्रयोग करें तो उप्र में किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक होने की क्षमता है। यह बात अपेक्स कमेटी के चेयरमैन एवं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डॉ.अरविंद सिंह ने आइवीआरआइ में पत्रकारों से कही। प्रधानमंत्री की किसान आय दोगुनी करने की घोषणा को हकीकत में बदलने के लिए अपेक्स कमेटी गठित की गई है।

श्री सिंह ने बताया कि आइसीएआर ने हर प्रदेश में भी अपेक्स कमेटी गठित की है। उप्र में 27 सदस्यीय कमेटी काम शुरू कर चुकी है। कमेटी में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण और कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं। पड़ोसी जनपद पीलीभीत निवासी डॉ. अरविंद सिंह ने किसानों को भगवान बताया। बोले, उनका उत्थान करना हम सभी का धर्म है। उप्र में थोड़े से प्रयास से किसानों की आय दोगुनी से अधिक हो सकती है।

आइवीआरआइ में प्रेसवार्ता करते डॉ. अरविंद सिंह • जागरण

कमेटी का दावा

- फसल उत्पादन बढ़ाने को संसाधन हैं पशुपालन को बढ़ावा देना भी जरूरी
- राष्ट्रीय स्तर से उप्र की फसल उत्पादकता कम

प्रस्ताव तैयारी के बारे में बताया कि वर्ष 2016-17 की किसान आय के बारे में जानकारी की जाएगी। इसके बाद फसल लागत कम कर आमदनी बढ़ानी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले, अब एक्शन मोड में आ गए हैं। जल्द प्रस्ताव तैयार कर इसे लागू कराया जाएगा। आय बढ़ाने को तकनीकी हस्तक्षेप करने की बात कही। किसान क्या तकनीकी सहायता ले रहे हैं, क्या ले सकते है और क्या फायदेमंद होगी।

आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देना भी जरूरी बताया। डॉ. अरविंद सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से उप्र में फसल उत्पादकता कम है जबकि यहां 75 फीसद पानी, अच्छी कृषि भूमि समेत सभी संसाधन हैं। गेहूं, धान और गन्ना पैदावार बढ़ने की उम्मीद जताई। पशु टीकाकरण पर भी जोर दिया। इस मौके पर आइवीआरआइ के निदेशक डॉ.आरके सिंह, डॉ.महेश चंद्र समेत तमाम प्रमुख लोग मौजूद थे।

एनजीओ की भी लेंगे मदद

कमेटी चेयरमैन ने एनजीओ से भी मदद लेने की बात कही। बोले, कृषि पर एनजीओ काफी काम कर रहे हैं। इसलिए किसानों की आय दोगुनी करने के प्रस्ताव को तैयार करने में एनजीओ की मदद लेंगे।

यह है अपेक्स कमेटी: 27 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.अरविंद सिंह और कन्वेनर आइवीआरआइ निदेशक डॉ.आरके सिंह हैं। इसमें सीएस आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एगरिक एंड टेक्नालॉजी कानपुर, एनडी यूनिवर्सिटी फैजाबाद, एसवीबीपी यूनिवर्सिटी मोदीपुरम, बांदा यूनिवर्सिटी बांदा, पंडित डीडीयू पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा के कुलपति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोड्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, डायरेक्टोरेट ऑफ सीड रिसर्च मऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ एगरी इम्पॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स मऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टीकल्चर लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबिल रिसर्च वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारमिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम्, सेंट्रल एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गोट्स मखदूम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर,, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ, कृषि विभाग लखनऊ, हार्टीकल्चर, मत्स्य विभाग और अटारी कानपुर के निदेशक सदस्य हैं। इसके साथ ही चार मंत्रालयों के सचिव को भी कमेटी में सदस्य की भूमिका दी गई है। कमेटी के यह सभी सदस्य दो दिन से मंथन में जुटे थे।

2022 तक किसानों की आय दो गुनी कराने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो
बरेली।

रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विवि के कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों की खेती से आमदनी दो गुना कराने के लिए 15 अप्रैल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। यहां के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मंगलवार को आईवीआरआई में प्रदेशभर के कृषि विवि के कुलपति की बैठक हुई। जिसमें कृषि मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग सहित सभी विशेषज्ञ वैज्ञानिक के सुझाव लिए गए। जिन पर 10 अप्रैल तक मंथन होगा और रिपोर्ट तैयार होगी । ऐसी ही रिपोर्ट देश के अन्य प्रांतों से भी तैयार होंगी और उनके आधार पर केंद्र सरकार किसानों की खेती से 2022 तक दो गुना आमदनी के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी।

पत्रकारों से वार्ता करते हुए कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार ने बताया कि कमेटी के समन्वयक आईवीआरआई के निदेशक प्रोफेसर आरके सिंह को बनाया गया है। अन्य विवि के कुलपतियों ने विशेषज्ञ के रूप में सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 27 फरवरी को बरेली में सभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी दो गुना करने की घोषणा की थी। जिस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से काम शुरू हो गया है। कानपुर के एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रदेश भर में कृषि उत्पादकता बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन विश्वविद्यालय के कुलपति रहे मौजूद

सीएस आजाद कृषि विवि कानपुर। नरेंद्र देव कृषि विवि फैजाबाद, एसवीबीपी विवि मोदीपुरम, बांदा कृषि विवि, चौधरी चरण सिंह कृषि विवि। प्रदेश सरकार के निदेशक सीड, निदेशक पशुपालन, निदेशक बागवानी, निदेशक मत्स्य, निदेशक खाद्य अनुसंधान संस्थान वाराणसी सहित 30 विशेषज्ञ शामिल थे।

आईवीआरआई में हुई बैठक, 15 अप्रैल को सौंपेंगे रिपोर्ट

कमेटी के अब तक के सुझाव

कृषि उत्पादन को तकनीक में सुधार। फ्रं टलाइन प्रदर्शन और विस्तार करना होगा। बीमार मिट्टी को स्वस्थ्य करने को परीक्षण अभियान ।अधिक उत्पादकता वाले बीज के इस्तेमाल को प्रोत्साहन। नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल, फसल बीमा की अनिवार्यता। कृषि उत्पादन के साथ-साथ फूड इंडस्ट्रीज को विकसित किया जाए। कृषि के साथ-साथ डेयरी पालन को बढ़ावा दें। पंजाब की तर्ज पर यूपी में गेहूं की उत्पादकता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो। गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र की तरह हो। प्रदेश में कृषि का 77 फीसदी हिस्सा सिंचित है, जिसका भरपूर इस्तेमाल करें।